

REMITTANCES BY FOREIGN OIL
COMPANIES

157. SHRI JAGDISH PRASAD
MATHUR:

SHRI NIREN GHOSH:

SHRI SASANKASEKHAR
SANYAL:

DR. E. MATHEW KURIAN:

Will the Minister of PETROLEUM
AND CHEMICALS AND MINES AND
METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gov-
ernment have asked the foreign oil
companies in India to review their
remittances abroad in respect of items
not covered by their agreements if so,
the details in this regard; and

(b) what was the amount of re-
mittances of the each of these com-
panies for the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN
THE MINISTRY OF PETROLEUM
AND CHEMICALS AND MINES AND
METALS (SHRI D. R. CHAVAN):

(a) Yes. The Oil Companies state that
they have not remitted any amount
not assured either by Refinery Agree-
ments or by the provisions of Foreign
Exchange Regulations.

(b) The total remittances made by
each of foreign oil companies during
1967, 1968 and 1969 were as follows:—

(Figures in Rs. Lakhs)

Year	Burmah Shell		Esso Standard		Caltex	
	Refining	Marketing	Refining	Marketing	Refining	Marketing
1967	901	3400	1715	471	979	230
1968	523	2899	2297	579	1757	96
1969	466	3810	2087	486	1288	44

दिल्ली में साबुन की कीमतों में वृद्धि

158. श्री सुरज प्रसाद : क्या पेट्रोल
तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में
दुकानदारों ने 15 अप्रैल, 1970 से साबुन
की कीमतों में 75 पैसे प्रति किलो की वृद्धि
कर दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने साबुन
निर्माताओं का कितने प्रतिशत मूल्य-वृद्धि
करने की अनुमति दी थी; और

(ग) क्या सरकार उचित मूल्य पर
साबुन बेचने के लिए दुकानदारों को कोई
आदेश देने का विचार रखती है ?

†[RISE IN SOAP PRICES IN DELHI

158. SHRI SURAJ PRASAD: Will
the Minister of PETROLEUM AND
CHEMICALS AND MINES AND
METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the
prices of soaps in general have been
raised by 75 paise per kilo by the
shopkeepers in Delhi with effect from
the 15th April, 1970;

(b) if so, what is the percentage of
increase allowed by Government to
the soap manufacturers; and

(c) whether Government propose
to issue any directive to the shop-
keepers to sell soap at reasonable
prices?]

†[] English translation.

पेट्रोल तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) ज्ञात हुआ है कि 15-4-1970 के बाद दिल्ली में दुकानदारों ने कपड़ा धोने के साबुन की कीमतों में वृद्धि कर दी है और यह वृद्धि प्रति किलोग्राम 20 पैसे से प्रति किलोग्राम 60 पैसे के बीच है।

(ख) साबुनों की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कारखानों में निर्मित साबुनों के मूल्यों पर अनौपचारिक नियंत्रण है जिसके अन्तर्गत उत्पादक, आयातित चर्बी, वनस्पति तेलों जैसे कच्चे मालों की लागत बढ़ जाने के कारण कीमतों में वृद्धि करने के लिए सरकार से अनुमति लेते हैं। बड़े-बड़े कारखानों द्वारा निर्मित साबुनों के मूल्य में 15-4-1970 से कोई वृद्धि करने की इजाजत नहीं दी गई थी। परन्तु 20-7-1970 से निम्नलिखित वृद्धियों की इजाजत दी गई थी :—

टायलट साबुन 5 पैसे—100 ग्राम की एक टिकिया पर

कार्बोलिक साबुन 4 पैसे—150 ग्राम की एक टिकिया पर

लांडरी साबुन 14 पैसे प्रति किलोग्राम

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता क्योंकि साबुनों के विक्रय मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH): (a) It is understood that the shopkeepers in Delhi have increased the prices of washing soap after 15th April, 1970 and the increase ranged from 20 paise per kg. to 60 paise per kg.]

†[] English translation.

(b) There is no statutory control on the prices of soaps. There is, however, an informal control on prices of soaps manufactured by the large scale sector, under which the manufacturers obtain the approval of Government for an increase in prices effected due to increase in cost of raw materials viz., imported tallow, vegetable oils. No increase in price of soaps manufactured by the large sector was allowed with effect from 15th April, 1970. Following increases were, however, allowed with effect from 20th July, 1970.

Toilet Soap—5 paise per cake of 100 gms.

Carbolic Soap—5 paise per cake of 150 gms.

Laundry Soap—14 paise per kg.

(c) No. Question does not arise as there is no statutory control on the selling prices of soaps.]

दिल्ली की गन्दी बस्तियों में मकानों का निर्माण

159. श्री सुरज प्रसाद : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में राजधानी की गन्दी बस्तियों में कुल कितने मकानों का निर्माण किया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) ऐसे कितने मकानों का आबंटन किया गया है और कितने अभी खाली पड़े हैं; और

(ग) सभी मकानों का शीघ्र आबंटन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?